ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की अनिवार्य तैनाती

2553. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत चिकित्सा कालेजों के सफल छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्षों तक कार्य करने को अनिवार्य बनाने से संबंधित कोई योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस विकल्प के अनुसार कोई योजना न तैयार करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद जो स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतियां निर्माण करने वाला निकाय है, के 8-10 जनवरी, 1997 को हुए पांचवें सम्मेलन में परिषद ने संकल्प किया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की रिक्तियां भरने के लिए क्षेत्रीय विकेन्द्रित भर्ती संबंधी नीति शुरू करने तथा 2-3 साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा शुरू करने पर विचार कर सकते हैं । परिषद ने यह भी संकल्प किया था कि स्नातकोत्तर सीटों की प्रतिशतता सेवाकालीन चिकित्सा अधिकारियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा आरक्षित की जा सकती है । सेवाकालीन डाक्टरों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्रता शर्त पांच वर्ष की सेवा की जा सकती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3 वर्ष की ग्रामीण सेवा शामिल है । रेगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों के मामले में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से दो वर्ष ग्रामीण सेवा के रूप में गिने जा सकते हैं । नीति को अपनाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है जिनमें से कुछ ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इस उपाय को कार्यान्वित करना शुरू किया है ।

Implementation of Health Projects in Orissa

2554. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the name of the health projects taken up in Orissa with the World Bank assistance;

(b) the amount of assistance provided by the World Bank to each of the projects;

(c) the extent to which each of the said projects has been successful; and

(d) the details of the specific steps being taken by Government to expedite implementation of each of the projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) There are no health sector projects taken up with World Bank assistance exclusively for the State of Orissa. However, Orissa is a participating state in the centrally sponsored World Bank aided Cataract Blindness Control Project, the National AIDS Control Project, the National Leprosy Elimination Project and the Child survival and Safe Mother hood (CSSM) programme. The last mentioned project is funded jointly by the World Bank and the